लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4146

19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जम्मू और कश्मीर में जूट बागानों की उत्पादकता बढ़ाना

4146. श्री जुगल किशोर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में जूट बागानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) जूट क्षेत्र के सतत विकास के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जूट बैगों की मांग बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जूट की खेती के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियां नहीं होने के कारण जूट उत्पादक राज्यों की श्रेणी में नहीं आता है।

(ख): सरकार वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 485.58 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से जूट क्षेत्र के समग्र विकास और संवर्धन के लिए एक व्यापक योजना -राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी) को कार्यान्वित कर रही है, जो इस क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करता है।

(ग): सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान के तहत पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसानों से लगभग 24.69 लाख क्विंटल कच्ची पटसन खरीदी है।

(घ): सरकारजूट उद्योग को बढ़ावा देने हेतु जूट बैगों की माँग बढ़ाने के लिए, जूट कारीगरों/उद्यमियों की भागीदारी में मदद करके हल्के वजन के कम लागत वाले जूट कैरी बैगों के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। यह स्थानीय निकायों/स्वैच्छिक संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सहयोग से जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करती है, तथा जूट शॉपिंग बैगों के डिसप्ले एवं प्रचार के माध्यम से क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी करती है।

*****